प्रदेश के सभी जिलों में बनेंगे एमएसएमई

बड़ी के साथ छोटी इकाइयों को मिलेगा बढ़ावा, जमीन के विकास पर 190 करोड़ होंगे खर्च

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने बड़ी के ही साथ छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण शुरुआत की है। बंद पड़ी सभी कताई मिलों की जमीनों पर क्लस्टर विकसित कर छोटी इकाइयों को दिए जाएंगे। न्यूनतम 500 मीटर से लेकर अधिकतम 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।

मऊ, रायबरेली, बाराबंकी, अलीगढ़, प्रतापगढ़, महोबा, प्रयागराज सहित अन्य जिलों में इस पर काम शुरू हो गया है। अगले पांच महीने में जमीनें आवंटित कर उद्यमियों को डीएम सर्किल रेट पर दी जाएंगी। जमीनों के विकास पर करीब 190 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस रकम से कम से कम 10,000 नई इकाइयों का क्लस्टर तैयार होगा।

इसके अतिरिक्त कब्जे वाली ग्राम समाज की जमीन को भी एमएसएमई विभाग खाली कराकर उसे विकसित कर स्थानीय छोटे उद्यमियों को आवंटित करेगा। रायबरेली, फतेहपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद और टूंडला सहित कई जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। बंद कताई मिलों और ग्राम समाज के कब्जे वाली जमीनों को एमएसएमई पार्क में तब्दील करने की ये पहल देश में पहली बार की गई है।

ये जमीनें मेरठ, हरदोई, झांसी, प्रयागराज, बांदा बलिया, मऊ, रायबरेली, बाराबंकी, अमरोहा, बरेली, गाजीपुर, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बिजनौर, संतकबीरनगर व बुलंदशहर जिले में हैं।

प्रतीकात्मक

बंद पड़ी कताई मिलों की जमीनों पर क्लस्टर विकसित कर छोटी इकाइयों को दिए जाएंगे

रायबरेली, बाराबंकी, अलीगढ़, प्रतापगढ़, महोबा, प्रयागराज सहित अन्य जिलों में काम शुरू

कताई मिलों की कुछ जमीनें मेडिकल कॉलेजों को दी गई हैं। मऊ और रायबरेली में क्रमशः 83 एकड़ और 43 एकड़ जमीन पर एमएसएमई पार्क बनाने की हरी झंडी मिल गई है। बाराबंकी में आईटी पार्क विकसित करने के लिए यूपीसीडा को जमीन दी गई है। अलीगढ़ में 45 हेक्टेयर, प्रतापगढ़ में 25 हेक्टेयर, महोबा में 12 हेक्टेयर और प्रयागराज में 11 हेक्टेयर जमीन पर पार्क बनेंगे।

ग्राम समाज की कब्जे वाली जमीनें की जाएंगी विकसित : ग्राम समाज की कब्जे वाली जमीनों को खाली कराकर उन्हें विकसित कर उद्यमियों को देने की मंजूरी मिल गई है। रायबरेली और फतेहपुर में 150 बीघा ग्राम समाज (जीएस) लैंड पर एमएसएमई पार्क बसाने का प्रस्ताव फाइनल है। इसी तरह अलीगढ़ में एमएसएमई पार्क बसाया जा रहा है। ये जमीनें वोकल फॉर लोकल के तहत पहले स्थानीय उद्यमियों को ही आवंटित की जाएंगी। फिरोजाबाद और टूंडला में भी इसी तर्ज पर जीएस लैंड पार्क विकसित किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला उद्योग अधिकारियों को इस काम में लगा दिया गया है। ब्यूरो

हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

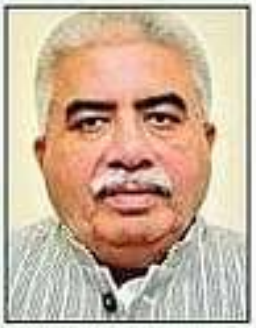

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कताई मिलों के साथ औद्योगिक आस्थानों की खाली जमीनें छोटे उद्यमियों को दी जाएंगी। इस दिशा में काम शुरू हो गया है। अगले पांच से छह महीनों में अधिकांश जिलों में एमएसएमई पार्क विकसित कर छोटे उद्यमियों को दे दिए जाएंगे। इस पहल से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और दस हजार छोटी इकाइयों का जन्म होगा।

– **राकेश सचान,** एमएसएमई मंत्री